

**Title:** Need to conduct a CBI enquiry into the reported stock-scam involving central cooperative Banks of Nagpur, Usmanabad and Wardha Districts of Maharashtra.

**श्री किरिीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के सभी अखबारों में पिछले पांच-सात दिनों से महाराष्ट्र में जो कोऑपरेटिव बैंक का और शेयर ब्रोकर का एक नया घोटाला लोगों के सामने आया है, उसके बारे में छप रहा है। मेरी जानकारी के हिसाब से डिपाजिटर्स के लगभग चार सौ करोड़ रुपये आज डूबने की स्थिति में है। इसमें महाराष्ट्र के चार बड़े कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष, वहां के विभिन्न राजकीय पक्षों के नेता हैं, ये पैसा उनके बैंकों में डूबने की स्थिति में है। उन्होंने स्टॉक ब्रोकर होम ट्रेड को किसी भी प्रकार की रिसीट लिये बगैर पैसा दिया। यह सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, गुजरात, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के कोऑपरेटिव बैंकों ने भी इस प्रकार से होम ट्रेड के उस ब्रोकर को पैसे दिये। कुल मिलाकर यह घोटाला लगभग छः सौ करोड़ रुपये का होने की संभावना है। इसमें स्माल डिपाजिटर्स का पैसा वापस मिलेगा या नहीं, इस संबंध में केन्द्र सरकार को स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता है। क्योंकि स्माल डिपाजिटर्स के एक लाख रुपये तक की डिपाजिट पर रिजर्व बैंक की कंपनी डिपाजिट इंश्योरेंस गारंटी कारपोरेशन की गारंटी होती है। लेकिन आज तक केन्द्र सरकार ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की है। मेरी प्रार्थना है कि केन्द्र सरकार इस संबंध में तुरंत स्थिति स्पष्ट करे।

इसके अतिरिक्त आज तक जिन बैंकों के नाम आये हैं, उनकी संख्या 17 से ज्यादा हो गई है और इस संबंध में राज्य सरकार ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। मैं यह मानता हूँ और मैं आज महाराष्ट्र सरकार की प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने 12 दिन रिजर्व बैंक का अहवाल अपने पास रखने के पश्चात सत्ताधारी एन.सी.पी. के एम.एल.ए. को अरेस्ट किया। लेकिन केवल यहां तक ही मामला सीमित रहने से काम नहीं चलेगा। मेरी केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि एक राज्य से अधिक राज्यों में यह क्राइम हुआ है, इसलिए यह मामला सी.बी.आई. को देना चाहिए। इसके साथ-साथ जो भी संबंधित गुनहगार हैं, उनके पासपोर्ट्स तुरंत जब्त करने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, केतन पारिख के पश्चात यह दूसरा सबसे बड़ा घोटाला है। कपूर कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें उन्होंने लिखा है - चार सौ में से 143 कोऑपरेटिव बैंक्स के सभी एकाउन्ट्स का इनवैस्टीगेशन होना चाहिए। मैं केन्द्र तथा राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि आर.बी.आई., नाबार्ड और राज्य सरकारों के जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, वे तुरंत इसमें कार्रवाई करें और बाकी और कौन से बैंक्स ने होम ट्रेड को पैसा दिया है, वह जानकारी लोगों के सामने रखी जाए। नागपुर में आज कोऑपरेटिव बैंक्स के बाहर हजारों इनवैस्टर्स अपना पैसा वापस लेने के लिए लाइनों में खड़े हैं। वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो रही है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से प्रार्थना करूँगा कि राज्य सरकार ने इसमें जो ढिलाई बरती है, उसमें भी ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार को दूसरी राज्य सरकारों को भी लिखना चाहिए कि वहां के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स को इसमें इनवैस्टीगेशन करना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि इस बारे में केन्द्र सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। उसकी ओर से किसी भी प्रकार की स्टेटमेंट नहीं आया है। हमने आर.बी.आई. और सेबी से मुलाकात की है, हम इसमें केन्द्र सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग करते हैं। केन्द्रीय मंत्री माननीय राम नाईक जी और महाराष्ट्र के डिप्टी लीडर यहां मौजूद हैं, इन दोनों को पता है कि वहां किस प्रकार की भयानक स्थिति है। लगभग चार लाख डिपाजिटर्स आज वहां आस लगाये बैठे हैं कि केन्द्र सरकार इसमें क्या भूमिका निभाती है। यह चार लाख परिवारों का मामला है। अगर केन्द्र और राज्य सरकार ने इसमें तुरंत अनाउंसमेंट नहीं किया तो बाकी कोऑपरेटिव बैंकों से लोग अपना डिपाजिट वापस लेने की शुरुआत करेंगे। इस तरह से गुजरात के बाद महाराष्ट्र में पूरा कोऑपरेटिव बैंकिंग सैक्टर भयंकर स्थिति में आयेगा। इसलिए केन्द्र सरकार को इस पर ध्यान देकर तुरंत अनाउंसमेंट करना चाहिए। यहां श्री राम नाईक जी मौजूद हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि इस मामले की क्या स्थिति है, उस बारे में वह बाद में निवेदन करें, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस संबंध में केन्द्र सरकार की ओर से निवेदन होना आवश्यक है। वह बाद में सदन को पूरी स्थिति की जानकारी दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद।

SHRI PRABODH PANDA : Hon. Deputy-Speaker, Sir, through you I would like to draw the kind attention of the House...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Panda, please wait. The hon. Member has raised a very important point.

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI RAM NAIK): Shri Kirit Somaiya has raised a very important issue. I would ensure that the Finance Minister is informed of what he has said as early as possible.